भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6205
जिसका उत्तर मंगलवार, 05 मई, 2015 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार

6205. श्री हुकुम सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को मजबूत बनाने के लिए महज 75 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इतने कम आवंटन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन का बाजार उच्च अग्रिम लागत, राजसहायता के संवितरण में देरी और अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, हां। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, सरकार ने 25.03.2015 को फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अंगीकरण और विनिर्माण] नामक एक स्कीम अधिसूचित की है। इस स्कीम के लिए सरकार ने ₹75 करोड़ का प्रारंभिक परिव्यय आबंटित किया है।

(ग): यह सत्य है कि चार्जिंग अवसंरचना की उच्च लागत तथा इसके अभाव के कारण इलेक्ट्रिक वाहन पर्याप्त बिक्री दर्ज नहीं कर पाए हैं। फेम-इंडिया स्कीम में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का समाधान करने का प्रयास किया गया है और इसके परिणामस्वरूप बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में वृद्धि होने की आशा है।

****